

श्रेष्ठ योजना

प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय शकषा नीति, श्रेष्ठ योजना ।

मेन्स के लयि:

शकषा, अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति से संबंघति मुद्दे, अनुसूचति वर्ग के लुगुं की सामाजकि और आर्थकि स्थिति के उत्थान में भारत सरकार की वभिनिन शैकषकि योजनाओं का युगदान ।

चर्चा में क्युं?

हाल ही में सामाजकि न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'श्रेष्ठ' योजना शुरु की है । इस योजना कु लकषति कषेत्रों में हाईस्कूल के छात्रों के लयि आवासीय शकषा योजना के रूप में जाना जाता है ।

- अनुसूचति जाति श्रेणी के छात्रों कु गुणवत्तापूर्ण शकषा और अवसर प्रदान करने के लकष्य के साथ 'श्रेष्ठ' योजना बनाई गई थी ।

'श्रेष्ठ' योजना:

परचिय:

- इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ नजि आवासीय वदियालयों में बच्चुं कु उच्च गुणवत्ता की शकषा प्रदान करके अनुसूचति जाति के लुगुं की सामाजकि-आर्थकि स्थिति का उत्थान करना है ।
- CBSE से संबंघ नजि स्कूलुं के कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान कयि जाएगा ।

उद्देश्य:

- सरकारी पहलुं और युगनाओं की आसान पहुँच सुनश्चति करना ।
- अनुसूचति जातयुं की सामाजकि-आर्थकि उन्नति और समग्र वकिस के लयि अनुकूल वातावरण तैयार करना ।
- शकषा कषेत्र में सेवा से वंचति अनुसूचति जाति (SC) के वर्चस्व वाले कषेत्रुं में अंतर कु पाटने के लयि स्वयंसेवी समूहों के साथ सहयुग करना ।
- युगय अनुसूचति जाति (SC) के छात्रुं कु उच्च गुणवत्ता वाली शकषा के साथ सकषम करना ताकवि भवषिय के अवसरुं का लाभ उठा सकुं ।

पात्रता:

- अनुसूचति जाति के छात्र कु वर्तमान शैकषणकि वर्ष (2021-22) में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ रहे हैं, युगना का लाभ उठाने के लयि पात्र हैं ।
- इसमें 2.5 लाख रुपए तक की वार्षकि आय वाले हाशयि के आय वर्ग से आने वाले अनुसूचति जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं ।
- चयन एक पारदर्शी तंत्र के माधयम से कयि जाएगा जसुं राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फ़ॉर श्रेष्ठ (NETS) के रूप में जाना जाता है ।
 - नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लयि इसका आयुगन कयि जाएगा ।

लाभार्थी:

- सरकार का लकष्य है कि इस प्रणाली के तहत हर साल SC वर्ग के लगभग 3000 छात्रुं कु कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दयि जाएगा ।
- मंत्रालय उनके शकषा और आवास शुल्क की पूरी लागत वहन करेगा जब तक कवि अपनी कक्षा 12वीं की शकषा पूरी नहीं कर लेते ।

SCs के लयि अन्य संबंघति पहलुं:

बाबू जगजीवन राम छात्रावास युगना (BJRCY):

- सामाजकि न्याय और अधिकारिता वभिग इस युगना के कार्यान्वयन के लयि एक नुडल एजेंसी है ।

- नए छात्रावासों के निर्माण के लिये केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)** के तहत नजीक क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों, अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों/डीमड विश्वविद्यालयों/अनुसूचित जातों के छात्रों के लिये मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

▪ **SCs के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ:**

- यह योजना **वर्ष 2006 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसे राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है।
- सरकार अपने प्रयासों में वृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है ताकि अनुसूचित जातों का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय मानकों तक पहुँच जाए।

▪ **एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना:**

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को योग्यता परीक्षा आयोजित करके योजना को लागू करने का काम सौंपा गया है।
- **लाभार्थी:** अनुसूचित जात, अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC), वमिकृत, खानाबदोश और घुमंतू जनजातों तथा आर्थिक रूप से पछिड़ी जातों (EBC) श्रेणियों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे।

स्रोत- पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/shreshta-scheme>

